

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध-21/2015-
प्रेषक,

2933

खाद्य, पटना/दिनांक- 20.06.18

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- 1. CWJC No. 19386/2017 शिव दुर्गा चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.02.2018 को निर्गत न्याय निर्णय।

2. विभागीय पत्रांक-407 दिनांक-24.01.2018 एवं 1479 दिनांक-20.03.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। उल्लेखनीय है कि CWJC No. 19386/2017 शिव दुर्गा चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.02.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए रद्द अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित मामले को ससमय निष्पादन कराने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु विगत कई मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा "बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के पूर्व स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी को जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि इसी तरह के एक अन्य मामला CWJC No. 1675/2018 मो0 अब्बास आलम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के आधार पर दिनांक 29.03.2018 को वादी के पक्ष में निर्णय दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः संलग्न न्याय निर्णय के आलोक में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के विरुद्ध अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व "बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति धारक को सांविधिक मानक (Statutory Norms) का अनुपालन सुनिश्चित करने, जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने का पर्याप्त समय मुहैया कराने हेतु अपने स्तर से अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

21/6/18
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- प्र07-विविध-21/2015-

2933

खाद्य, पटना/दिनांक- 20.06.18

प्रतिलिपि - अनुलग्नक सहित सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/18
सरकार के सचिव।

99

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.1675 of 2018

=====

Md. Abbas Alam @ Abbas Alam, Son of Late Zahir Alam, Resident of Village - Farreh, P.S.-Chautham, Distt.-Khagaria.

..... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Secretary Food and Consumer Protection Department, Old Secretariat, Patna.
2. The Collector, Khagaria
3. The Sub-Divisional Officer, Khagaria.
4. The Block Supply Officer, Chautham, District Khagaria.

..... Respondents

=====

Appearance :

For the Petitioner : Mr. Dhananjaya Nath Tiwari, Advocate.

For the Respondents : Mr. S. Raza Ahmad, AAG-5

=====

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE VIKASH JAIN

ORAL JUDGMENT

Date: 29-03-2018

Heard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the respondents.

2. The present writ petition has been filed for setting aside the order contained in Memo no. 491 dated 18.08.2009 passed by learned S.D.O., Khagaria by which the PDS license of the petitioner being license no. 23 C/2007 has been cancelled; and further for quashing the order dated 12.09.2017 passed in Supply Appeal Case No. 12/2013 passed by the learned Collector, Khagaria by which the statutory appeal was dismissed.

3. Learned counsel for the petitioner makes a short submission to assail the impugned order on the ground that a copy of the enquiry report was not made available to the petitioner and he was



never confronted with the same with an opportunity of being heard or adducing evidence in that regard. A specific stand has been taken in paragraph-13 of the writ petition that the impugned order of cancellation of licence has been passed without providing a copy of the enquiry report to the petitioner, though the same has been relied upon in the impugned order. Such infirmity could not be cured in the appeal.

4. Learned counsel for the respondents appears and has been heard. The stand of the petitioner with regard to non-supply of enquiry report has not been controverted, as no counter affidavit has been filed till date.

5. In the above view of the matter, this Court is satisfied that non-supply of the enquiry report to the petitioner has resulted in violation of natural justice and thus the decision making process stands vitiated. The impugned order dated 18.08.2009 (Annexure-5) and the appellate order dated 12.09.2017 (Annexure-6) are hereby quashed and the matter is remanded to the Sub-Divisional Officer, Khagaria, for taking decision afresh in the matter after supplying a copy of the enquiry report to the petitioner and granting an opportunity of hearing in accordance with law. Supplies to the petitioner shall be restored without delay until fresh orders are passed by the respondent no. 3.

6. It is made clear that in case the stand of the petitioner denying receipt of the enquiry report prior to order of cancellation being passed is found to be incorrect, the respondents shall be at



97

liberty to approach this Court for recall of this judgment.

7. The writ petition stands allowed as above.

(Vikash Jain, J)

Md. Ibrarul/BT

AFR/NAFR	NAFR
CAV DATE	N.A.
Uploading Date	30.03.2018
Transmission Date	N.A.

